(b) by when Government propose to get such allottee shifted to ease the tension prevailing in the area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRl DALBIR SINGH): (a) A request through Member of Parliament has been forwarded from the 'All India CPWD Employees Union.

(b) The matter is being looked into.

Maintenance of Tube Wells/Pumps in Pushp Vihar, New Delhi

3389. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any rule under which Construction Divisions of CPWD handover their work to Maintenance Divisions after a prescribed period; if so, the period prescribed for the purpose;

(b) what are the reasons that work relating to maintenance of the tube wells/Pumps in Pushp Vihar, New Delhi have not been handed over by the Electrical Construction Division-IV to Electrical Maintenance Divi-sion-XIII so far even after lapse of more than 6 years; and

(c) by when Government propose to get the work handed over to the said Maintenance Division?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) There is no such rule.

(b) The Electrical Division No. XIII, which is not a purely maintenance Division, is very heavily loaded and hence not in a position to take up any additional work. Accordingly, the Elect. Constn. Division, which is comparatively light, is continuing to maintain wells/pumps in Pushp Vihar.

(c) There is no such proposal.

उचित दर की दुकानों में अनियमितताएं

3390. **श्री रामसिंहभाई पातलीया-भाई राठवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली, गुजरात तथा अन्य राज्यों के लोगों से 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1986 की अवधि में उचित दर की दुकानों में हेराफेरी, अनियमितता, कालाबाजारी और धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस संबंध में सुधार करने के लिए क्या नये उपाय किये गये हैं ;

(ङ) क्या सरकार वर्तमान वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं भी उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) चूंकि अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन और प्रशासन के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं, अतः हेराफेरी, अनियमितताओं, चोर-बाजारी और धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निपटाई जाती हैं । केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है ।

(ग) और (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जांच की व्यवस्था करते हैं और उचित कार्यवाही, जिसमें जहां कहीं आवश्यक हो वहां लाइसेंस को रद्द करना भी शामिल है करते हैं । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं । राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों